a foreign collaboration approval and letter of intent on the 23rd and 26th April, 1993 respectively, for setting up a joint venture with 50% equity participation as a new undertaking at permissible location in India for the manufacture of tobacco/cigarettes subject to the condition that they shall make maximum use of local tobacco. Only *6%* of the requirement of tobacco will be imported over a period of five years.

The foreign partners will assist the Indian Joint Venture in undertaking an extensive agricultural development programme to develop existing types and grades of higher qualities. They will also assist in providing seedling production techniques to farmers, development of disease resistant varieties and local processing facilities and locating new export markets.

Closure of P.S.Us. in Bihar and West Bengal

982. SHRI GAYA SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some Public Sector Undertaking* are likely to be closed down in Bihar and West Bengal; and

(lb) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Based on performance of Central Public Enterprises during 1991-92, 19 Central PSEs having their registered office in West Bengal and 5 Central PSEs having their registered office in Bihar have been identified as industrially sick and referred to BIFR for their revival/rehabilitation. BIFR have recommended the closure of the following two PSEs in West Bengal:

1. Cycle Corporation of India Ltd.
2. Weighbird India Ltd.

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योग

983. श्री गया सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें इस स्थिति से उबारने/बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 50 उद्यमों को औद्योगिक रूप से रुग्ण अभिज्ञात किया गया है और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 44 रुग्ण उद्यमों को उनके लिये पुनरुद्धार/पुर्नस्थापन सम्बन्धी पेकेज बनाने के लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास पंजीकृत किया गया है। सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या तो स्वतः ही अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निवेदन पर उनकी पुनरुद्धार सम्बन्धी योजना की जांच भी कर सकता है।

अनिवासी भारतियों द्वारा भारत में निवेश की पेशकश

984. श्री गया सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत अब तक कितने अनिवासी भारतियों ने भारत में निवेश करने की पेशकश की है; और

(ख) इस संबंध में बिहार की स्थिति सहित ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद